भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2021

दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

चारा संकट

2021 श्री सतीश चंद्र दूबेः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरे चारे, सूखे चारे और गाढ़े चारे के मामले में क्रमशः12-15, 25-26 और 36 प्रतिशत चारे की कमी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में चारे की कमी के विभिन्न कारणों का आकलन किया है और यदि हाँ, तो देश में चारे की कमी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का चारा क्षेत्र बढ़ाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) भाकृअनुप-भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान (आईजीएफआरआई) ने अनुमान लगाया है कि देश में हरे चारे, सूखे चारे और कंसंट्रेट्स की क्रमशः 11.24%, 23.4% और 28.9% कमी है।

(ख) और (ग). देश में चारे की कमी के विभिन्न कारण भूमि उपयोग के पैटर्न में बदलाव चारा खेती वाले क्षेत्र में कमी, शहरीकरण, चरागाहों की घटती उत्पादकता, वाणिज्य फसलों की ओर भूमि का विपथन, फसल अवशेषों का अन्य औद्योगिक उपयोग के लिए विपथन, गुणवत्तायुक्त चारे के बीजों की अनुपलब्धता, पशुओं की उन्नत उत्पादकता से चारे की बढ़ती मांग हैं।

पशुपालन राज्य का विषय है; फसलों के पैटर्न में चारा फसलों को बढ़ावा देना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' और 'पशुपालन अवसंरचना विकास निधि' को लागू करके राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है। देश में राष्ट्रीय पशुधन मिशन चल रहा है, जिसमें नकदी फसल के रुप में चारा फसल को बढ़ावा देने वाली उच्च उपज वाली चारा किस्मों के बीज उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार चारा फसलों की खेती के तहत और अधिक क्षेत्र में विविधता आयेगी। 50 लाख रु. तक 50% सब्सिडी प्रदान करके चारा ब्लॉकों/हे बेलिंग/साइलेज इकाइयों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। गुणवत्तायुक्त पशु चारे का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए पशु चारा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना सहित पशु चारा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। भाकृअनुप-भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी द्वारा 20 राज्यों के लिए तैयार की गई चारा संसाधन योजनाओं को भी इनके कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ साझा किया गया है। मुख्य रूप से चारा केंद्रित और सहायक रूप में पशुपालन कार्यकलापों के लिए 100 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन की योजना के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है। ये चारा प्लस एफपीओ चारा विकास संबंधी विभिन्न कार्यकलाप करेंगे जैसे हरा चारा/साइलेज का उत्पादन और बिक्री, 'रेडी-टू-ईट' टीएमआर का उत्पादन, फसल अवशेषों को प्राप्त करना तथा उसकी बिक्री और पशुपालन संबंधी अन्य कार्यकलाप जिससे छोटे और सीमांत किसानों को बाजार पहुंच उपलब्ध हो सके।

****